

# सरकारी नौकरी दी, फिर सेवा से पृथक किया, वेतन भी नहीं दिया? - खुशमारदन

न्यायसाक्षी/रायगढ़

सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में पीड़ित खुशमारदन ने बताया गया कि मैं खुशमारदन लड़का आ अवर्दिया लड़का, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम तुमला, पो तुमला, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर छ.ग, से हूँ और मुझे सरकारी सेवा से पृथक कर दिया गया है, वेतन भी नहीं मिला है, अतः न्यायोचित कार्यवाही कराकर न्याय दिलाया जावे, साथ में उसके द्वारा विनासुर जारी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

खुशमारदन ने कहा कि मुझे दिनांक 27/11/2012 का के कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर छ.ग के अदेश क्र /1 761 जिपं/स्था/मनसा/2012 के अनुसार ग्राम कुडबहाल, डाकघर तुमला, तह. फरसाबहार, जिला जशपुर छ.ग. में लेखापाल के पद पर पद नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे सप्त होता रहा, और मेरे विरुद्ध अध्यात्मा मुझे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे सप्त होता रहा, और मेरी नियुक्ति वैधानिक रूप से पृथक कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है व्यक्ति इस सेवाकाल में मुझे शासन के नियमों के तहत भुगतान प्राप्त होता रहा, और मेरे विरुद्ध अध्यात्मा मुझे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे सप्त होता रहा, और मेरी नियुक्ति वैधानिक रूप से पृथक कर दिया गया है।



28/02/2014 तक के लिए

से हुई थी। पीड़ित ने कहा कि यह योजना शासन की थी, जिसके सम्बन्ध में शासन के नियमानुसार नौकरी लाने के आदेश के पालनार्थ नियुक्ति की गई थी, सप्त है कि मैं शासन का कर्मचारी था, और मुझे शासन के नियमानुसार भुगतान प्राप्त होता था। यह भी कि उक्त रिक्तियों के लिए मैं उचित तरीके से चयनित होकर आया था, और मैंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ नियमानुसार, जो कि इस कथन से भी प्रमाणित है कि मूझको किसी कारण बताता होता सूचना अधि, एकीकृत बाल विकास परियोजना, ताका, को मैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। सामाजिक न्याय संघ ने कहा कि माननीय उच्चतम् एव उच्च न्यायालयों के विनियोगी आदेशों का भी उल्लेख किया जाने उपर्युक्त है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी योजना के समाप्त होने पर सरकार कर्तव्यों की नौकरी समाप्त नहीं कर सकती, अपितु कार्य के लिए एवं प्रयुक्त उन कर्मविधियों को, जो कि उक्त योजना के तहत नियुक्त किए गए थे, को समायोजित करने की पूर्ण नियमानुसारी सरकार की होती, और सरकार इससे मुख्य फैर नहीं सकती है। इस प्रकरण में नैतिक न्याय के तहत कार्यवाही लेनी जाएगी अतः इस प्रकरण को पुनः अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है।

पीड़ित ने कहा कि मुझे अन्याकृत तरीके से चयनित होकर आया था, और मैंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ नियमानुसार, जिसका वेतन भी मुझे आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया। मुझे 18/07/2014 को सेवा से पृथक कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है व्यक्ति इस सेवाकाल में तहत भुगतान प्राप्त होता रहा, और मेरे विरुद्ध अध्यात्मा मुझे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे सप्त होता रहा, और मेरी नियुक्ति वैधानिक रूप से पृथक कर दिया गया है।

पीड़ित ने कहा कि मुझे अन्याकृत तरीके से चयनित होकर आया था, और मैंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ नियमानुसार, जिसका वेतन भी मुझे आज दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया। मुझे 18/07/2014 को सेवा से पृथक कर दिया गया, जो कि न्यायोचित नहीं है व्यक्ति इस सेवाकाल में तहत भुगतान प्राप्त होता रहा, और मेरे विरुद्ध अध्यात्मा मुझे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे सप्त होता रहा, और मेरी नियुक्ति वैधानिक रूप से पृथक कर दिया गया है।

## एस.जे.यू. से की शिकायत

गैरे प्रकरण के सापेख में मुझे तकाल न्यायिक सहयोग दिया जाकर न्यायोचित क्रियानंवल करा के सेवा में लिए जाने एवं संदर्भित वेतन दिलाए जाने की कृपा की गयी। मैं बहुत पीड़ित हूँ, असलाय हूँ, मुझे मेरे घर-परिवार द्वारा रखने की आवश्यकता है, आवश्यक न्यायोचित कार्यवाही कर मेरी मदद की जावे। इसी प्रार्थना के साथ यह आवेदन मैं अपने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं।

## नहीं हुई कोई कार्यवाही

राज्यपाल, गुरुद्वारी छग शासन, अंजय चंद्राकर, मन्त्री, कलेक्टर, जशपुर, अनुविभागी अधिकारी (राज्य) कुठकुरी, जशपुर, परियोजना अधि, एकीकृत बाल विकास परियोजना, ताका, को मैं लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। सामाजिक न्याय संघ ने कहा कि माननीय उच्चतम् एव उच्च न्यायालयों के विनियोगी आदेशों का भी उल्लेख किया जाने उपर्युक्त है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी योजना के समाप्त होने पर सरकार कर्तव्यों की नौकरी समाप्त नहीं कर सकती, अपितु कार्य के लिए एवं प्रयुक्त उन कर्मविधियों को, जो कि उक्त योजना के तहत नियुक्त किए गए थे, को समायोजित करने की पूर्ण नियमानुसारी सरकार की होती, और सरकार इससे मुख्य फैर नहीं सकती है। इस प्रकरण में नैतिक न्याय के तहत कार्यवाही लेनी जाएगी अतः इस प्रकरण को पुनः अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है।

भी कोई भी कारण बताओं न्यायोचित नहीं है। जिस हेतु नोटिस मिलता है। मैंने अपनी मुझे यह आवेदन सामाजिक सेवाएं पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी न्याय संघ के माध्यम से से की और उसके बाद मुझे प्रस्तुत किए जाने की मेरी सेवा से पृथक कर देना आवश्यकता हुई।

## और एक शिकायत चिटफंड कम्पनी ए.ए.पी.एल. कोलकाता के विरुद्ध

चिटफंड में इन्वेस्ट रकम को वापस दिलाने हेतु शासन गंभीर नहीं? नामजद रिपोर्ट होने पर भी भला तर्ह नहीं करती पुलिस कार्यवाही?



न्यायसाक्षी/रायगढ़।

शासन से मान्यता प्राप्त

संस्था सोशल जस्टिस

रूनियन के समक्ष प्रस्तुत

होकर दिए अपने लिखित

आवेदन में बताया गया कि

चिटफंड कम्पनी "अग्रदूत

एजेंसीसी प्राइवेट लिमिटेड

कोलकाता" द्वारा

7,1500/- अक्षरांक सात

लाख पन्द्रह हजार रुपये

जमा रखने, 3 महीने के बाद

रकम वापस करने एवं इस

सम्बन्ध में 6 प्रतिशत व्याज

के आश्वासन देने के बाद भी,

रकम पर व्याज नहीं दी जा

रही, उन्होंने रकम मूलधन

को मांगे जाने पर नहीं दिए

जाने की स्थिति में, विधिक

सहायता प्रदान कराए जाने

हेतु भी नियोदहन किया है।

अपने आवेदन में "बुधानाथ

राम" आ. लालकरे राम, उम्र

32 वर्ष निवासी ग्राम

आम्बाटोली, पो. जांमचुआ,

थाना नारायणपुर, जिला जशपुर,

छ.ग. पिन 496225, ने बताया

कि मुझे अमरदास के द्वारा फैन

करके बुलाया गया था, मेरे

पहुँचने पर उक्त अमरदास के

साथ वर्हां अरविंद सिंह भी

उपर्युक्त है। जिसके द्वारा मूलधन के साथ संतुष्ट हो गया और अपने गांव के लोग है, धोखा नहीं होना सोचकर मेरे द्वारा

रुपये 5000/- रुपये अक्षरांक सात

रुपये अक्षरांक सात हजार

रुपये अक्षरांक सात हज